



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938

No. 31]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

मामला सं. OI/04/2017

विषय : चीन जन. गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

फा सं. 14/49/2016-डीजीएडी.—यतः, मै. आलोक इंडस्ट्री लि., मै. इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि. और मै. बॉम्बे डार्इंग एंड मेन्यु. कं. लि. (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता या 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से '0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पालिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) (रीसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाइबर अर्थात् केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटारडेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाइबर को छोड़कर)' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

क. कथित रूप से पाटित किया जा रहा उत्पाद और समान वस्तु

2. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया गया है कि ऊपर उल्लिखित देशों से '0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पालिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) (रीसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाइबर अर्थात् केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटारडेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाइबर को छोड़कर)' का आयात हो रहा है और वे भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे आयातों से समान उत्पाद के घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

3. उक्त उत्पादों को उनके डेनियर, मजबूती, चमक (जैसे सेमी डल, चमकदार, सेमी ब्राइट, फुल डल आदि), रंग, क्रास सेक्शन और कट लेंथ या स्टेपल लेंथ के अनुसार विभिन्न विनिर्देशनों में विनिर्मित किया जाता है। संबद्ध वस्तु को अधिकांशतः 100 प्रतिशत पीएसएफ के स्पिन यार्न या वस्त्र, सिलाई धागे, अन्य औद्योगिक वस्त्रों, गैर-वोवेन अनुप्रयोगों आदि के विनिर्माण के लिए प्राकृतिक, कृत्रिम और/या सिंथेटिक स्टेपल फाइबर में प्रयोग किया जाता है।

4. आवेदकों ने आगे यह अनुरोध किया है कि आवेदक भारत में उक्त वस्तु का उत्पादन करते हैं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये वस्तुएं रसायनिक और भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता घरेलू और आयातित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अर्थ के भीतर ये 'समान वस्तु' हैं।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह आवेदन संयुक्त रूप से मै. आलोक इंडस्ट्री लि., मै. इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि. और मै. बॉम्बे डार्इंग एंड मेन्यु. कं. लि. द्वारा दायर किया गया है जिनका संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा बनता है। पूर्वोक्त उत्पादकों के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात् मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) है जिसका कुल घरेलू उत्पादन में शेष 57 प्रतिशत हिस्सा बनता है। प्राधिकारी को यह बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मलेशिया में एक संबंधित उत्पादक अर्थात् मै. रेक्रान मलेशिया एसडीएन बीएचडी. है जो संबद्ध वस्तु का एक निर्यातक है और उसने जॉच की प्रस्तावित अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसलिए आरआईएल नियमावली के नियम 2(ख) में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर शामिल किए जाने की पात्र नहीं है।

6. उक्त सूचना और नियम की स्थिति के अनुसार, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह मानते हैं कि आरआईएल नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने के पात्र नहीं हैं। इसलिए आवेदकों का पात्र घरेलू उत्पादन के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है और वे क्षति जॉच के प्रयोजनार्थ नियम 2 (ख) में यथा परिभाषित के अनुसार अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। उनका संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में भी प्रमुख हिस्सा है और इसलिए नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन दायर करने की योग्यता रखते हैं। अतः आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दायर किया गया माना गया है।

ग. जॉच किए जाने वाले देश

7. वर्तमान जॉच चीन जन. गण. इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटित आयातों के संबंध में है। इन देशों से आयातों की मात्रा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है। उक्त देशों के अलावा, कोरिया गणराज्य और ताइवान से न्यूनतम सीमा से अधिक आयात हुए हैं। तथापि ये आयात काफी अधिक कीमतों पर हैं। अतः, इन देशों को जॉच के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

घ. पाटन का साक्ष्य

8. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान उन देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित कीमतों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत, सबसे अधिक कार्यकुशल घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और विधिवत रूप से समायोजित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

9. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु की निवल कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत जॉच की प्रस्तावित अवधि के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेस (आईबीआईएस) से प्राप्त आयात आकड़ों के आधार पर अनुमानित की गई है जिसमें समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभार और वैट समायोजन, जहां लागू हो को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के उक्त अनुमान से पता चलता है कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात काफी पाटित कीमतों पर किया जा रहा है और पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

11. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत के संचयी प्रभाव के कारण वास्तविक क्षति हुई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि जाँच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और मांग और देश में क्षमता की उपलब्धता में मामूली वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग कम रहा है। कीमत प्राप्ति भी बिक्री लागत से काफी कम रही है जिसका स्पष्ट कारण पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव रहे हैं जिनसे भारी वित्तीय घाटा हुआ है जबकि उत्पादकता और बिक्री में सुधार हुआ है। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आवेदक घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों के कारण ऋणात्मक लाभ और निवेशों पर ऋणात्मक आय के कारण वास्तविक क्षति हो रही है।

च. जाँच की शुरुआत

12. और यतः उक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जाँच की शुरुआत करते हैं।

i. विचाराधीन उत्पाद

13. इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

'0.6 से 6 डेनियर की रेंज के नान-डाइड पालिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) (रीसाइकल्ड पीएसएफ और विशेष फाइबर अर्थात् केटिओनिक डाइयेबल, फायर/फ्लेम रीटार्डेंट, लो मैल्ट और बायो कम्पोनेंट फाइबर को छोड़कर)'

14. उक्त उत्पादों को उनके डेनियर, मजबूती, चमक (जैसे सेमी डल, चमकदार, सेमी ब्राइट, फुल डल आदि), रंग, क्रास सेक्शन और कट लेंथ या स्टेपल लेंथ के अनुसार विभिन्न विनिर्देशनों में विनिर्मित किया जाता है। इस जाँच में उक्त उल्लिखित अपवर्जनों को छोड़कर ऐसे सभी प्रकार के उत्पाद शामिल होंगे।

15. संबद्ध वस्तु को अध्याय 55032000 – 'सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, कार्डेड नहीं, काम्ब्ड या अन्यथा पालिएस्टर की स्पिनिंग के लिए प्रसंस्कृत' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ii. जाँच की अवधि (पीओआई)

16. इस जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अप्रैल 2015 से 30 सितंबर, 2016 तक (18 महीनों) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015 और जाँच अवधि के आकड़े शामिल होंगे।

iii. सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थापित उनके दूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

dgad.india@gov.in

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

iv. समय-सीमा

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के चालीस (40) दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर और तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

20. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को इस सूचना के पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर अपने उत्तर अलग-अलग प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग सूचित किया जा रहा है।

21. यह नोट किया जाए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

v. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को किए गए अनुरोधों को अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा। जिसे अन्य हितबद्ध पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी मूल प्रति के साथ दो-दो (2) प्रतियों में दोनों अंशों की साफ्ट प्रतियां भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

23. दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना हो सकती है जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता व्यापार संवेदी सूचना होने का दावा करता है जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना के प्रदाता का वाणिज्यिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे। स्वाभाविक रूप से गोपनीय और गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जाँच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

vi. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

vii. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

[DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES]

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2017

Case No. OI/04/2017**Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.**

F. No. 14/49/2016-DGAD.—Whereas, M/s Alok Industry Ltd., M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd. and M/s The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd., (hereinafter also referred to as ‘petitioners’ or ‘applicants’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules”) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers (excluding recycled PSF and specialty fibres namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres)” from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.

A. Product allegedly being dumped and like Article

2. The petitioners have alleged imports of “Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers (excluding recycled PSF and specialty fibres namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres)” from the countries named above are entering the Indian market at dumped prices and such imports are causing injury to the like product domestic industry.

3. The above products are manufactured in various specifications defined in terms of their deniers, strength, lustres (like semi dull, bright, semi bright, full dull etc.), colour, cross section and cut length or staple length. The subject goods are predominantly used to spin yarn of 100% PSF or in blends with natural, artificial and/or synthetic staple fibres for manufacture of textiles, sewing thread, other industrial textiles, non-woven applications, etc.

4. The applicants have further submitted that the applicants produce the above goods in India and there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioners. The goods are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications. Consumers use the domestic and imported goods interchangeably. The products are technically and commercially substitutable and therefore, ‘like article’ as per the meaning of the term under the Rules

B. Domestic Industry & Standing

5. The Application has been jointly filed by M/s Alok Industry Ltd., M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd. and M/s The Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd., accounting for about 43% of total domestic production of the subject goods. Apart from the aforesaid producers there is one more producer of the subject goods in India, namely M/s Reliance Industries Ltd.(RIL), which accounts for the remaining 57% of total domestic production. It has been brought to the notice of the Authority that Reliance Industries Limited has a related producer in Malaysia, namely M/s Recron Malaysia Sdn Bhd., who is an exporter of the subject goods and has exported the subject goods to India during the proposed period of investigation. Therefore, RIL is not qualified to be included within the scope of the ‘domestic industry’ as defined in Rule 2(b) of the Rules.

6. In view of the above information and the Rule position, the Authority *prima facie* holds that RIL is not eligible to be considered as a part of the eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules. Therefore, the applicants, commanding 100% of the total production of the eligible domestic production, constitute the domestic industry within the meaning of the term as defined in Rule 2(b) for the purpose of injury investigation. They also account for a major proportion of the domestic production of the subject goods and therefore, command the standing to file the application in terms of Rule 5(3) of the Rules. Therefore, the application is deemed to have been made by and on behalf of the domestic industry.

C. Countries to be investigated

7. The present investigation is in respect of alleged dumped imports of the product under consideration from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand. (hereinafter also referred to as the subject countries). The volume of imports from these countries are above the *de minimis* limit prescribed. Apart from the above countries, there are above *de minimis* imports from Korea RP and Taiwan. However, these imports are significantly higher prices. Therefore, these countries have not been included in the scope of this investigation.

D. Evidence of Dumping

8. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production, taking into account prevailing prices of raw materials and utilities in those countries, conversion costs of the most efficient domestic industry, and duly adjusted selling, general & administration expenses, plus a reasonable profit.

9. Net ex-works export prices of the subject goods exported from the subject countries have been estimated on the basis of import data obtained from International Business Information Services (IBIS) for the proposed period of investigation after due adjustments toward ocean freight and marine insurance; port expenses, inland freight, commission and bank charges; and VAT adjustments, wherever applicable on facts available basis.

10. The above estimation of the Normal Values and Export Prices indicates that there is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being exported from the subject countries to India at significantly dumped prices and the dumping margins are above *de-minimis*.

E. Evidence of Injury and Causal Link

11. The applicants have claimed that they have suffered material injury because of cumulative volume and price impacts of the dumped imports from the subject countries. Information provided by the petitioners indicates that there has been significant rise in the volume of dumped imports during the period under examination and in spite of moderate growth in demand and availability of capacity in the country, the production and capacity utilization of the domestic industry has remained low. The price realization also continues to be significantly below the cost of sales, apparently because of the volume and price effects of dumped imports leading to significant financial losses, in spite of improvement in productivity and sales. Therefore, *prima facie* it appears that the applicant domestic industry is suffering material injury in terms of negative profits and negative return on investments due to the volume and price effects of the dumped imports from the subject countries.

F. Initiation of the Investigation

12. **And Whereas**, having regard to the above Rules, the Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

i. Product under investigation

13. The product under consideration (hereinafter also referred to as 'subject goods) in this investigation is defined as follows:

“Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) ranging from 0.6 to 6 Deniers (excluding recycled PSF and specialty fibres namely, Cationic Dyeable, Fire/Flame Retardant, Low Melt and Bi-component Fibres)”.

14. Non-dyed Polyester Staple Fibre (PSF) is manufactured in various specifications defined in terms of their deniers, strength/tenacity, lustres (like semi dull, bright, semi bright, full dull etc.), colour, cross section and cut length or staple lengths. The investigation shall cover all such product types, except the exclusive exclusions indicated above.

15. The subject goods are classified under chapter 55032000 - “Man Made Staple Fibres of Synthetic Staple Fibres, Not Carded, Combed or Otherwise Processed for Spinning of Polyesters”. The custom classification above is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in this investigation.

ii. Period of Investigation (POI)

16. The period of investigation for the purpose of this investigation shall be from 1st April 2015 to 30th September, 2016 (18 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, April 2014 to March 2015, and POI.

iii. Submission of Information

17. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the known importers and users in India, and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address, so as to enable the Authority make appropriate determinations in a timely manner:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce,

Jeevan Tara Building, 4th Floor,

Parliament Street, New Delhi -110001

dgad.india@gov.in

18. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the Authority at (www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

iv. Time Limit

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

20. The exporters/importers and other interested parties, being notified individually may file their responses within forty days (40 days) from the date of the letter of intimation to be addressed to them separately.

21. It may be noted that if no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

v. Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority, including questionnaire response on confidential basis, are required to file a non-confidential version of the submissions made, which will be made available to all other interested parties to make their comments. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked so at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

24. The confidential version may contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as business proprietary information, disclosure of which will adversely affect the commercial interest of the supplier of such information. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out. In case indexation is not feasible, the information may be summarized, depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either not willing to make the information public, or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

vi. Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by all interested parties to the investigation.

vii. Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available with it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority